सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-5 8 मार्च से 22 मार्च 2017 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

विश्व सर्वहारा के महान नेता
कार्ल मार्क्स जिन्दाबाद !

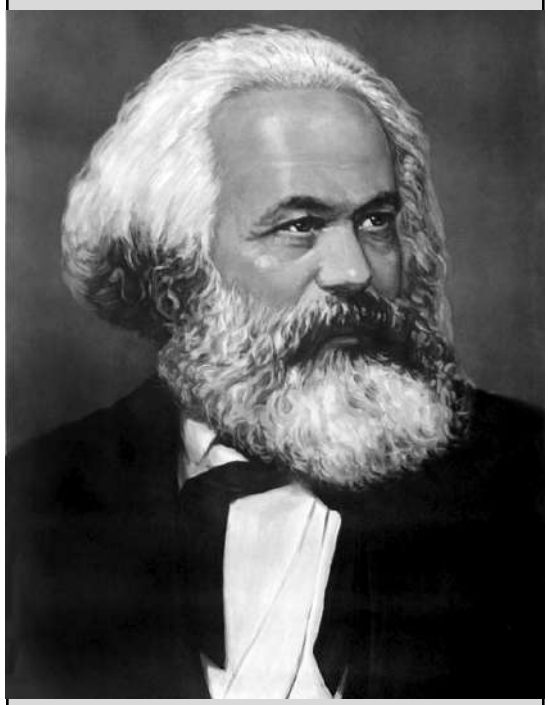

5-5-1818 14-3-1883

''कोई भी समाज व्यवस्था तब तक खत्म नहीं होती, जब तक उसके अन्दर तमाम उत्पादन शक्तियां, जिनके लिए उसमें जगह है, विकसित नहीं हो जाती और नये, उच्चतर उत्पादन सम्बन्धों का आविर्भाव तब तक नहीं होता जब तक कि उनके अस्तित्व की भौतिक परिस्थितियां पुराने समाज के गर्भ में ही पुष्ट नहीं हो चुकती। इसलिए मानवजाति अपने लिए हमेशा केवल ऐसे ही कार्यभार निर्धारित करती है, जिन्हें वह सम्पन्न कर सकती है। कारण यह कि मामले को गौर से देखने पर हमेशा हम यही पायेंगे कि स्वयं कार्यभार केवल तभी उपस्थित होता है, जब उसे सम्पन्न करने के लिए जरूरी भौतिक परिस्थितियां पहले से तैयार होती हैं, या कम से कम तैयार हो रही होती हैं।''

– कार्ल मार्क्स 'राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा के एक प्रयास की भूमिका'

जनतंत्र के मुखौटे के पीछे से

आरएसएस-भाजपा के कृत्यों और जुमलों में सुनाई दे रही है पूंजीपतियों को बचाने के लिए फासीवादीकरण के कदमों की आहट

मुट्ठीभर अरबपति जहाँ आनन्द मना रहे हैं वहीं चुपचाप लेकिन निश्चित तौर पर करोड़ों करोड़ लोगों पर मनहूसियत का काला साया गहराता जा रहा है। जहाँ बुर्जुआ डैमोक्रेसी की पवित्र नियम-पुस्तक (संविधान) दावा करती है कि ''लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए'' और जहाँ विस्तारित होती साम्राज्यवादी दुनिया, भारत के बाजार पर धावा बोलने के लिए सबसे बड़े जनतंत्रों में से एक बताते हुए इसकी बड़ाई करती है। वहीं भारत के हैरान-परेशान लोग जो अभी भी दिलो दिमाग में इंसानियत का जज्बा रखते हैं, यह देख कर हक्के बक्के हैं कि किस प्रकार अथाह असमानता प्रयास कर रही है समानता को ग्रसित करने का, कि किस हद तक वंचना आम लोगों को अमानवीय अस्तित्व के गर्त में धकेल सकती है, लोगों के जीवन को अव्यवस्था और फूट से तबाह करने के लिए असहिष्णुता और तर्कहीनता कितना अनिष्टकारी आयाम अख्तियार कर सकती है।

राष्ट्र-विरोधी साम्प्रदायिक रुझान के साथ हुआ आरएसएस का उदय

कहने की जरूरत नहीं है कि एक रात में तो इतनी अनिष्टकारी काली छाया पैदा नहीं हो सकती है। इसके लिए सालों साल लगे हैं जिनके जरिए लोगों को जीवन के प्रत्येक पहलू में अधिक से अधिक दुख-तकलीफों और दुर्दशा में धकेला गया है। इन सबके ऊपर रही है एक घातक शक्ति आर.एस.एस. की गतिविधियाँ, जो अपने घोर साम्प्रदायिक हिन्दुत्व के सिद्धान्त के साथ उस समय अस्तित्व में आई जब सारा देश राष्ट्रीय आजादी की खातिर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ रहा था। सावरकर जिसे आर.एस.एस. वीर कहती है के विभाजनकारी विचार के आधार पर कि ''सिर्फ हिन्दुओं को ही इस देश के नागरिक होने का अधिकार है'' और यह कि ''हिन्दू और मुसलमान दो विरोधात्मक राष्ट्र हैं जो भारत में एक साथ अवस्थान कर रहे हैं।'' आर.एस.एस. के गुरु एम.एस. गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पर कहा था, ''ब्रिटिशवाद-विरोध को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बराबर बताना 'प्रतिक्रियावादी' है''। उन्होंने कहा था, ''हिन्दुस्तान में विदेशी नस्लों को हिन्दू राष्ट्र का महिमागान करने के सिवाय और किसी विचार का पोषण नहीं करना चाहिए और अपने अलग अस्तित्व को मिटा देना चाहिए; या वे हिन्दू राष्ट्र के पूरी तरह मातहत रह कर, कोई भी, यहाँ तक नागरिकों के अधिकार का भी दावा न जताते हुए देश में रह सकते हैं।'' वे नाजी सुप्रीमो हिटलर से ज्यादा हट कर नहीं थे। जब उन्होंने कहा ''अपनी नस्ल और संस्कृति की पवित्रता को कायम रखने के लिए जर्मनी ने अपने देश का शुद्धीकरण करके दुनिया को दहला दिया ... नस्ल गौरव अपनी पराकाष्ठा पर; हिन्दुस्तान में इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा सबक जिसे सीखना और लाभान्वित होना चाहिए।''

ऐसे एक राष्ट्र-विरोधी, फासीवादी, साम्प्रदायिक सिद्धांत से बंधे होने की वजह से आर.एस.एस.-हिन्दू महासभा और उनके अन्य सहयोगियों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया, 1942 में हुए भारत छोड़ो ऐतिहासिक आन्दोलन में भी नहीं जिसने देश को झकझोर दिया था और ब्रिटिश शासन को भी हिलाकर रख दिया था बल्कि आर.एस.एस. ने गौ-वध, उर्दू भाषा इत्यादि के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था, नियमित रूप से मुस्लिम विरोधी-दंगे संगठित करने लगे। अपनी वैमनस्यपूर्ण गतिविधियों और विचारों को निरंतर अंजाम देते हुए, आर.एस.एस. जैसी एक घातक कट्टरपंथी, अमानवीय घोर साम्प्रदायिक शक्ति चुपचाप मौके के इंतजार में रही। अपने राजनैतिक संगठनों पहले जनसंघ और बाद में भाजपा के माध्यम से, राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने के लिए इन्होंने तमाम हथकण्डों का इस्तेमाल किया। अंततः तत्कालीन तथाकथित नरम हिन्दुत्व की बदौलत और सीपीआई-सीपीआई(एम) जैसे स्वयंभू मार्क्सवादियों की पूर्णतः रीढ़विहीन वोट आधारित समझौतापरस्त सोशल डैमोक्रेटिक राजनीति की बदौलत भाजपा सत्ता के पायदान पर पहुंच गई। भाजपा पहले गठबंधन राजनीति का माध्यम अपनाते हुए 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरपरस्ती में एन.डी.ए. सरकार और फिर विपक्ष की राजनीति करते हुए 10 साल बाद 2014 में मोदी संचालित सिंगल पार्टी बहुमत के साथ सत्तासीन हुई।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

श्रमिक अधिकार दिवस पर रैली कर आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं ने सौंपा मांगों का ज्ञापन

नई दिल्ली : एआईयूटीयूसी से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं आदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई श्रमिक संगठन 1 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पर इकट्ठा हुए और एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में कॉ. एम. चौरसिया, सुधा, ममता राव, रीना, निर्मल, कन्हैया व राकेश शामिल थे। उसके बाद मजदूरों का जुलूस उपराज्यपाल आवास की ओर चल पड़ा। उनमें दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसियेशन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन, दिल्ली राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण वर्कर्स यूनियन, कर्मकार एकता केन्द्र, अरूणा आसफ अली वर्कर्स यूनियन, जी. बी. पन्त पैरामेडिकल स्टाफ यूनियन व अन्य संगठन शामिल थे। जूलूस का नेतृत्व एआईयूटीयूसी के सचिवमण्डल सदस्य कॉ. रमेश शर्मा, दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य कॉ. भंवरपाल, बक्शी, राकेश, रामकरण, ऐ.के. रावत, दिल्ली राज्य सचिव सह दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसियेशन के कॉ. एम. चौरसिया।, आंगनबाड़ी इम्पलाइज फेडरेशन की जगवन्ती, मिड-डे मील कामगार यूनियन की शिक्षा राणा और भवन एवं संनिर्माण वर्कर्स यूनियन के निर्मल सिंह ने किया।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

फासीवादीकरण के कदमों की आहट

देश को कर दिया आरएसएस की साम्प्रदायिक व देशविरोधी ताकतों के हवाले

(पृष्ठ 1 का शेष)

देश को कर दिया आर.एस.एस.-भाजपा के हवाले

भाजपा के सत्तासीन होने के साथ ही साथ एक विशाल देश जो परम्परागत रूप से अपने बहु-धर्मीय, बहुजातीय, बहु-भाषीय चरित्र के लिए और बहुत सारी कमियों के बावजूद एक डैमोक्रेटिक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता था। इसे आर.एस.एस. के हवाले कर दिया गया। उनके एजेण्डे को अब और छुपा कर रखने की जरूरत नहीं थी। उनको और उनके एजेण्डे को संरक्षण देने और आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ कुछ राज्य सरकारों, सारांश में कहें तो पूरे सत्ता तंत्र की ताकत उनके पास थी। उस एजेण्डे पर उन्होंने जोरदार ढंग से काम शुरू कर दिया जिसका तरीका रहा : टारगेट को कोने में धकेल देना और दुश्मन करार देना-आम तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को-धमकाने और भयभीत करने के लिए अंततः किसी भी हद तक हिंसा पर उतारु हो जाना जिसमें हत्या भी शामिल है। हालांकि कुछ समय के बाद किसी सक्रिय हिंसा की जरूरत नहीं रहेगी। हिंसा का तसव्वुर ही कोने में धकेल देगा और बैर-भाव को बढ़ा देगा। अंततः यह एक इलाके या क्षेत्र से निशाने पर आए एक समुदाय के पलायन या पूरी तरह से आत्मसमर्पण की ओर भी ले जाएगा।

केन्द्र में प्रथम भाजपा-नीत सरकार के समय गुजरात में, मौजूदा प्रधानमंत्री राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी द्वारा इस एजेण्डे को अंजाम दिया गया था। सन् 2002 में अत्यंत सुविचारित योजना के साथ पैशाचिक मुस्लिम-विरोधी गुजरात नरसंहार को अंजाम दिया गया था। जिसको गुजरात के साथ-साथ केन्द्र दोनों के पूरे प्रशासन और सरकारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन प्राप्त था। कुछ उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, तत्कालीन गुजरात सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी जो इस नरसंहार का समर्थन नहीं कर सके थे बाद में इसे उजागर किया। लक्षित अल्पसंख्यक समुदाय के छिन्नमूल हो जाने, बेरहमी से हत्या कर दिए जाने, पूरी तरह से भयाक्रांत करने और अचल कर देने के बाद ही केन्द्रीय भाजपा सरकार और इसके कर्णधार वाजपेयी ने दबी जुबान से राजधर्म निभाने की याद दिलाते हुए राज्य सरकार को लोग दिखावा फटकार लगाई थी।

अतंतः भारतीय पूंजीवाद की इस घोर संकट की घड़ी में साम्राज्यवादी विस्तारवाद की आकांक्षाओं के साथ जब शासक एकाधिकारी पूंजीपतियों ने देखा कि उनकी भरोसेमंद कांग्रेस पार्टी लम्बे अर्से से कुशासन और भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे होने की वजह से पूरी तरह बदनाम हो गई तो वे अपने एक अन्य भरोसेमंद राजनीतिक चेहरे भाजपा की ओर झुक गए। साम्राज्यवादी लॉबियों सहित भारतीय एकाधिकारी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के एक सशक्त तबके ने उनके वर्ग स्वार्थ को साधने और सेवा करने में मोदी की क्षमता और तत्परता को संज्ञान में लिया। चाशनी लिपटे शब्दों और झूठे वायदों के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने के साथ-साथ आर.एस.एस. की जहरीली लाइन के अनुरूप घातक साम्प्रदायिक लाइनों पर लोगों का ध्रुवीकरण करते हुए मेहनतकश जनता के बीच स्थायी फूट डालने की मोदी की काबिलियत का भी उन्होंने संज्ञान लिया। 'विकास पुरुष' के रूप में कार्य करने में सक्षम 'मजबूत प्रशासक' के रूप में और एक 'दूरदृष्टा राष्ट्र निर्माता' के रूप में मोदी की छवि के इर्द-गिर्द एक आभामण्डल तैयार करने के लिए उन्होंने सावधानीपूर्वक और बड़ी चालाकी से अपने ताबेदार मीडिया और प्रचार एजेंसियों का इस्तेमाल किया। कहने की जरूरत नहीं है कि उनका उद्देश्य था अपने घृणित वर्ग एजेण्डे को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाना, 'अच्छे दिन' के धुंआधार प्रचार के जरिए गरीबों और वंचितों को झांसा देना और साथ-ही-साथ साम्प्रदायिक भावनाओं को निरन्तर भड़काते हुए उनकी एकता को भंग करना। साथ ही साथ मध्यम वर्ग को लुभाने की एक भावी सुनियोजित योजना थी जिसे धीरे-धीरे हिन्दुत्व-केन्द्रित सामाजिक आधिपत्य के थीम को स्वीकार करने के लिए बदला जा सकता है। इस उद्देश्य की खातिर गरीब लोगों को गुमराह करने के लिए चाय बेचने वाले के रूप में उसकी शुरूआती मामूली पृष्ठभूमि को उछाला गया ताकि वे उसे अपने आदमी के रूप में स्वीकार कर लें जबकि एक कट्टर और आक्रामक आर.एस.एस. कार्यकर्ता के रूप में उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग और प्रतिबद्धता योजना में पूरी तरह फिट बैठती थी। इसके बाद लोगों के अधिक से अधिक शोषण के जरिए संकटग्रस्त पूंजीवादी शासन को बनाए रखने के स्वार्थ में दो तरफा प्रयास हुआ। एक तरफ आर.एस.एस. या कहिए संघ परिवार ने विभिन्न माध्यमों के जरिए हिन्दुत्व राजनीति के अपने दृढ़निश्चयी लक्ष्य के विचार को प्रचारित करना शुरू कर दिया ताकि देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदतरीन साम्प्रदायिक माहौल के साथ बिगाड़ते हुए इस पर एक सर्वव्यापक हिन्दुत्व आधिपत्य थोपा जा सके। दूसरी तरफ मोदी को विकास पुरुष के रूप में प्रोजेक्ट किया गया कि यह जनता के हित में कदम उठाएगा जबकि अंततः और वास्तविकता में यह शासक एकाधिकारी पूंजीपतियों और बेरहम शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था के सम्पूर्ण हित में काम कर रहा है।

आर.एस.एस. के उभार का मायना है डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता व भाईचारे का खात्मा

यह जल्द ही साफ हो गया कि यह उनके उभार का समय है। मोदी के सत्ता पर आसीन होने के ठीक पहले यू.पी. के मुज्जफरनगर में पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकित करने के लिए और बहुसंख्यक समुदाय के अन्दर घिनौना साम्प्रदायिक जहर भरने के लिए शातिराना ढंग से सुनियोजित और प्रायोजित भीषण साम्प्रदायिक दंगे करवाए गए। इसने पीड़ितों को तबाह कर दिया और भाजपा को विजेता बना दिया। नियंत्रित करनेवाला कोई नहीं। इसलिए एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई अल्पसंख्यक प्रताड़ना के नए से नए तरीके खोजने के लिए मुद्दे तलाशे या पैदा किए जाते रहे।

देश के अलग-अलग हिस्सों से गौ-मांस खाने या गौ-हत्या के झूठे आरोप लगा कर दलितों के साथ-साथ मुस्लिमों को प्रताड़ित करने यहाँ तक कि पीट-पीट कर मार देने की खबरे आने लगीं। साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिए मन्दिरों में गौ-मांस फैंकते हुए बुर्का पहने आर.एस.एस. के लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। 'लव जिहाद' का एक नया जुमला उछाला गया हिन्दुत्ववादी संगठन अल्पसंख्यक समुदाय पर आरोप लगाने लगे कि वे हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के साथ भागने में मदद कर रहे हैं। एक पूर्णतः निराधार, तर्कहीन यहाँ तक कि संख्या वृद्धि का मनगढंत आरोप मुस्लिमों पर मढ़ा जा रहा है और यह कि इससे ही लोगों की दुख-तकलीफें बढ़ रही हैं। सर्वविदित है कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने खुली सभाओं में इस तरह के मुस्लिम-विरोधी द्वेषपूर्ण अभियान को चलाया हुआ है। इस बारे में निराधार अफवाहें फैलाई गई कि एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिमों द्वारा कथित आतंकवादियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों पर कल्पित हमलों या अल्पसंख्यक लोगों द्वारा हिन्दुओं से सम्पत्ति छीनने के कथित आरोपों के बारे में नियमित रूप से कहानियाँ प्रचारित की जा रही हैं और इस बहाने मुस्लिमों या इसाइयों की सम्पत्तियों की तोड़-फोड़ की जा रही है। कुछ गाँवों में गैर-हिन्दुओं या उनके संगठनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिन्दू धर्म में विश्वास रखने के बावजदू भी गाँवों में दलितों को क्रूरतापूर्ण बहिष्कृत किया जा रहा है। तथ्यों की जांच किए बिना ही एक सुविचारित व सुनियोजित हो-हल्ला मचाया जा रहा है कि हिन्दुओं का दूसरे धर्मों में धर्मांतरण कराया जा रहा है। फिर इन सबको बहाना बनाकर अल्पसंख्यकों के शुद्धिकरण के लिए अभियान चलाया जाता है या घर वापसी कराई जाती है। कभी धमकी या प्रलोभन के बल पर कभी इसके बिना भी यह किया जाता है। स्कूलों में हिन्दू कर्मकाण्डों को अनिवार्य बनाया जा रहा है। कॉलेजों में प्रचार चलाया जा रहा है कि मुस्लिमों की वजह से हिन्दू छात्रों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यूनिवर्सिटी छात्रों में कहीं दलितों और कहीं वामपंथियों को प्रताड़ित किया जाता है कि वे सरकार के प्रति आलोचनात्मक विचार रखते हैं। यह सिर्फ भाजपा की छात्र शाखा द्वारा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि अॅथोरिटियों, स्थानीय आर.एस.एस.-भाजपा नेताओं के साथ-साथ केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा भी किया जा रहा है। प्रताड़ित करने, तंग करने और भेदभाव करने की वजह से 'हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए उकसाना इसकी एक मुँह बोलती मिसाल है। जे.एन.यू. के मुस्लिम छात्र नजीब की 'रहस्यमयी गुमशुदगी' की घटना एक दूसरा उदाहरण है। एक के बाद एक फ्री रेडिकल थिंकरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और हत्या कर दी गई। हाल ही में सावरकर या गोलवलकर जैसे अपने आकाओं द्वारा स्थापित सैद्धान्तिक आधार का अनुसरण करते हुए मौजूदा आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत ने किसी संयम या लेशमात्र भद्रता के बिना यह आह्वान किया कि हिन्दू राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश भर में हिन्दुओं का सशक्तीकरण किया जाना चाहिए। खेदजनक है कि उन्होंने इस सत्य को छुपाया कि जो सिद्धांत वे प्रचारित कर रहे हैं उसका आधार और कुछ नहीं बल्कि मुस्लिमों के प्रति नफरत और दुश्मनी है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक निजीकरण व व्यापारीकरण तथा गरीब परिवारों से आए छात्रों के लिए शिक्षा का अधिकार छीनने वाली शर्मनाक भेदभावपूर्ण नीति से भी बढ़कर आर.एस.एस.-भाजपा गठजोड़ नग्न रूप से शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थानों की स्वायत्तता का हनन कर रहा है, वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी शिक्षा की भयावह कीमत पर पाठ्य पुस्तक को और पाठ्यक्रमों में साम्प्रदायिक चिन्तन और विचारों को घुसेड़ रहा है। देश को तर्कहीनता, असहिष्णुता और घृणित साम्प्रदायिकता के आगोश में धकेलने के लिए जी-तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं। तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष, नजरिया, साम्प्रदायिक सद्भाव, जनवादी मानदण्ड और अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि दीर्घकालिक संघर्षों के माध्यम से जिस हद तक भी हासिल की गई थी उनका अधिकाधिक हनन किया गया और किया जा रहा है। जिन लोगों में थोड़ी बहुत भी तर्कबुद्धि है वे भौचक्के हैं। आम आदमी पूरी तरह किंकर्त्तव्यविमूढ़ है। आखिरकार यह वही देश है जहाँ व्यापक पैमाने पर लोग अन्याय, भेदभाव और वंचना के खिलाफ प्रतिवाद में उठ खड़े होते थे। फिर कहाँ गलती हो गई? जाहिरा तौर पर शक्तिशाली ताकतें जो वामपंथ की पैरोकार थी और अक्सर विशाल जुझारू आन्दोलनों में लोगों का नेतृत्व किया था, इसमें कुछ वक्त लगा और हो सकता है लोगों के समझने की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है कि ये तथाकथित बड़ी वामपंथी पार्टियाँ और कुछ नहीं बल्कि सोशल डैमोक्रेटिक ताकतें हैं जो लोगों के बढ़ते असंतोष का इस्तेमाल करती रही हैं, उत्तेजनाएं भड़काती रही हैं लोगों को अंतहीन रैलियों में शामिल कराती रही हैं लेकिन अंततः सबका अंत चुनावों के संघर्षों में हो जाता है। जो संसदीय व्यवस्था लोगों को अंधकार के गर्त में धकेल रही है उसी संसदीय व्यवस्था से सत्ता और धन पाने की लालसा उनके सारे जुझारूपन को ठण्डा कर देती है। पूंजीवाद के असमाधेय संकट की इस घड़ी में संसदीय

(शेष पृष्ठ 4 पर)

देश भर में शहीद चन्द्रशेखर आजाद को दी गई श्रद्धांजली

अहमदाबाद (गुजरात) : 27 फरवरी को शहीद चन्द्रशेखर आजाद का 86वां बलिदान दिवस ऑल इण्डिया डीएसओ और ऑल इण्डिया डीवाईओ द्वारा अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत आदि विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम कर सम्मान के साथ मनाया गया जिनमें शहीद को श्रद्धांजली दी गई।

अहमदाबाद में हर साल की तरह इस साल भी पार्क में नियमित आने वाले लोगों और छात्र-नौजवानों ने चन्द्रशेखर आजाद गार्डन में उनकी मूर्ति पर पुष्पांजली अर्पित की। इस अवसर पर ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा शहीद चन्द्रशेखर आजाद के जीवन-संघर्ष पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन जानी-मानी हस्ती और सेवानिवृत इंजीनियर श्री प्रहलादराय ने किया। क्रान्तिकारी गाने गाये गये और 'इन्कलाब जिन्दाबाद', 'शहीद चन्द्रशेखर आजाद अमर रहें' के नारे लगाये गये। इसके अलावा नर्मद मेघानी लाइब्रेरी में भी पुष्पांजली कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ोदरा में एम एस यूनिवर्सिटी में और शहर में कई जगहों पर तथा सूरत में मजदूर बस्ती में विविध कार्यक्रम किये गये। ऑल इण्डिया डीवाईओ के राज्य सचिव कॉमरेड जयेश पटेल और ऑल इण्डिया डीएसओ की राज्य सचिव कॉ. रिम्मी वाघेला ने बात रखी।

पिलानी (राजस्थान) 27 फरवरी को शहीद चन्द्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस स्थानीय वाल्मिकी बस्ती में मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देश भक्तिपूर्ण क्रान्तिकारी गीत गाये गए। कई प्रेरक कविताएं सुनाई गई। कार्यकक्रम के आयोजन में महावीर शर्मा, विष्णु वर्मा और फणी मणी ने प्रमुख भूमिका अदा की। विष्णु शर्मा ने आजादी आन्दोलन के महान क्रान्तिकारी शहीद चन्द्रशेखर आजाद के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में जन समस्याओं के समाधान का रास्ता क्या हो और छात्र-नौजवानों का फर्ज क्या है - यह बताया।

दुर्ग (छत्तीसगढ़) : शराब-विरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले 27 फरवरी को राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग करते हुए एक विशाल जुलूस निकाला गया। डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। महिला प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाये : 'नोटबंदी हो सकती है तो शराबबंदी क्यों नहीं'। बहुत अर्सा पहले कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया और 14 साल की बीजेपी सरकार द्वारा बढ़ाया गया शराब का कारोबार 3900 करोड़ रुपये हो गया है जो 6 साल पहले जितना था उसका छह गुना है। वैध-अवैध रूप से गांव-शहर में यह आसानी से उपलब्ध है। शराब माफिया ताकतवर गुण्डे बनकर उभर चुका है। लोग इस लत के ज्यादा से ज्यादा शिकार होते जा रहे हैं। इसके दुष्परिणाम स्वरूप परिवार उजड़ रहे हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, महिला के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इससे प्रदेश भर में लोगों, खासकर महिलाओं में रोष व्याप्त है। सरकार शराब बिक्री के कारोबार के पक्ष में डट कर खड़ी है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा की सरकार है। इस सरकार के खिलाफ आन्दोलन जारी है और पूर्ण शराबबंदी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। महिलाओं ने शराब नहीं बिकने देने का दृढ़ संकल्प ले लिया है।

नरेला (दिल्ली) एआईडीएसओ की तरफ से शहीद चन्द्रशेखर आजाद का शहादत दिवस स्थानीय गौतम कालोनी में मनाया गया। इस अवसर पर जनसभा की गई और 'महिला अदालत' नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन भारत माता स्कूल, नरेला की प्रिंसिपल शारदा दीक्षित जी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एआईडीएसओ के अखिल भारतीय कमेटी के कार्यालय सचिव कॉ. चंचल घोष थे और वक्ता दिल्ली राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष कॉ. राहुल सरकार थे।

सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता कॉ. चंचल घोष ने कहा कि आज इन क्रान्तिकारियों का कथन अक्षरशः सही साबित हो गया है कि केवल अंग्रेजों को देश से भगा देने से ही छात्र-नौजवानों, किसान-मजदूरों और महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। आजादी के 70 सालों के बाद भी ना शिक्षा सभी को मिल पाई, ना रोजगार ना ईलाज। माँ-बहनों की इज्जत आबरू पर जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं, यदि हमें इन सारी समस्याओं का हल करना है तो हमें उस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा जो शहीद चन्द्रशेखर आजाद जैसे क्रान्तिकारियों ने शुरू की थी। नाटक टीम में प्रतिभा, दिव्या, आयुशी, स्वीटी आदि सहभागी थे। कार्यक्रम के समापन में सारिका मैडम ने 'उठो ए साथियों मिलकर नया भारत बनाएंगे' गीत गया।

सोनीपत (हरियाणा) 26 फरवरी को चन्द्रशेखर आजाद की 86वीं शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर भटगांव में एआईडीएसओ की तरफ से खेल प्रतियोगिता में 3 ग्रुपों का लोंग जम्प और एक फुटबाल मैच का आयोजन किया गया। लोंग जम्प के लिए 8-10 वर्ष, 11-13 वर्ष और 14-16 वर्ष के बच्चों के ग्रुप बनाए गए थे। तीनों ग्रुपों के प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को पदक और फुटबाल विजेता टीम को ट्राफी देकर एआईडीएसओ के अखिल भारतीय कमेटी के कार्यालय सचिव कॉ. चंचल घोष ने खिलाड़ियों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि शहीद चन्द्रशेखर आजाद भी हष्ट-पुष्ट थे। वे नियमित रूप से अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए शारिरिक व्यायाम करते थे। इसलिए हमें भी सामाजिक काम में भागीदार बनने के लिए, शिक्षा पर हो रहे हमलों से लड़ने के लिए तथा रोजगार के गहराते संकट के खिलाफ लड़ने के लिए खेलकूद भी नियमित रूप से करना चाहिए ताकि हम अपने आप को वर्तमान व्यवस्था से लड़ने के लिए शारिरिक रूप से मजबूत बना सकें।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद के 86वें शहादत दिवस की पूर्वसंध्या 26 फरवरी को एआईडीएसओ, एआईडीवाईओ तथा नौजवान भारत सभा की तरफ से शहर में बाइक रैली निकाली गई जो महलाना चौक से शुरू होकर छोटूराम चौक, पुरखास अड्डा, गीता भवन चौक, बस अड्डा, ऑल्ड डी.सी. रोड, आईटीआई चौक से होते हुए महलाना चौक पर ही समाप्त हुई। बाइक रैली में सभी युवक 'शहीद चन्द्रशेखर आजाद अमर रहे', 'क्रान्तिकारियों की जीवनी को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दो', 'इन्कलाब-जिन्दाबाद,' 'अशिक्षा-बेरोजगारी के खिलाफ जन आन्दोलन तेज करो' तथा 'मेहनतकश का भाईचारा जिन्दाबाद' आदि नारे लगाते हुए धीरे-धीरे आगे बढते गये।

27 फरवरी को हिन्दू शिक्षण संस्था में चन्द्रशेखर आजाद के जीवन-संघर्ष को याद करने और उनके क्रान्तिकारी चरित्र से सीख लेने के लिए उनके 86वें शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन निखिल और तनवी सचदेवा ने किया।

छात्रों ने भिन्न-भिन्न माध्यमों से जैसे भाषण, कविता, देश भक्ति गीत, गजल आदि प्रस्तुतियों के द्वारा चन्द्रशेखर आजाद के विचारों को छात्रों तक पहुँचाया। इस कार्यक्रम में अमित, शिवानी, रितु शर्मा, प्रवेश, अतुल, विजय, कीर्ति, भारत आदि छात्रों ने अपनी प्रस्तुति देकर उनके विचारों को आगे ले जाने का अदम्य कार्य किया।

27 फरवरी को एआईडीएसओ और छात्र एकता मंच द्वारा स्थानीय सी.आर.ए. कालेज में चन्द्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर किये गये कार्यक्रम का संचालन एआईडीएसओ की सी.आर.ए. कालेज यूनिट के इन्चार्ज राजेश कुमार ने किया। कार्यक्रम में एआईडीएसओ के जिला सचिव प्रवीण नाहरा और छात्र एकता मंच की तरफ से सुमित कुमार ने व्यक्तव्य रखा। इस कार्यक्रम में सचिन, दीपक, दीक्षु, रवीन्द्र आदि शामिल थे।

18 फरवरी को गोहाना के गांव सैनीपूरा में सैनी ऑक्सफोर्ड सिनियर सैकण्डरी स्कूल में शहीद चन्द्रशेखर आजाद स्मृति सभा की गई। कार्यक्रम का संचालन जिला कमेटी के सदस्य राजेश कुमार द्वारा किया गया और जिला सचिव प्रवीण नाहरा ने अपना व्यक्तव्य रखा।

सोनीपत में बाइक रैली करते हुए छात्र- नौजवान

छात्रवृत्ति में भारी कटौती का विरोध

जमशेदपुर (झारखण्ड) : भाजपा-नीत झारखण्ड सरकार ने हाल ही में स्टाइफण्ड या छात्रवृत्ति में भारी कटौती कर दी है। पिछले साल ये राशि 50,000 रुपये थी, इस साल इसे घटाकर 15,000रुपये कर दिया गया है। झारखण्ड के गरीब छात्रों से शिक्षा छीन कर ये किस विकास की बात कर रहे हैं। रघुवर दासजी झारखण्ड को कहां ले जा रहे हैं? तस्वीर में 22 फरवरी को एआईडीएसओ की ओर से जमशेदपुर डीसी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र।

किसानों ने सौंपा ज्ञापन

भिवानी (हरियाणा) : 15 फरवरी को ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) जिला भिवानी की तरफ से किसानों व खेत-मजदूरों की समस्याओं को लेकर उपायुक्त महोदय भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा 40,000 रुपये प्रति एकड़ देने, किसान-विरोधी फसल बीमा योजना रद्द करने, आवारा पशुओं का प्रबन्ध करने, खेती में सब्सिड़ी बहाल करने, गरीब किसानों के हर प्रकार के कर्जे माफ करने, खेती में प्रयोग किये जाने वाले डीजल, डी.ए.पी., यूरिया, कीटनाशकों व कृषि औजारों की कीमत कम करने, किसानों को फसल के लाभकारी दाम देने, खेतीहर मजदूरों को पूरा साल काम देने, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 600 रुपए प्रतिदिन करने, शिक्षा-इलाज सस्ता करने की मांग की गई।

इससे पहले सैकड़ों किसान-खेतमजदूर स्थानीय नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए। वहां सभा हुई और फिर शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालते हुए लघु सचिवालय पहुँचे। धरने को संगठन के जिला प्रधान कॉमरेड जिले सिंह के अलावा उपप्रधान कामरेड सुखबीर सिंह, उदयबीर सिंह और जिला सचिव कॉ. रोहतास सिंह ने सम्बोधित किया। झज्जर में भी धरना दिया गया।

फासीवादीकरण के कदमों की आहट

संकीर्ण तबकाती जातिवादी-साम्प्रदायिक राजनीति व शासक पूंजीपतियों के समर्थन से अब तक कांग्रेस, भाजपा, सपा व बसपा के बीच घूमती रही सत्ता

(पृष्ठ 2 का शेष)

जनतंत्र में खुद के लिए जगह बनाने की जितनी अधिक कोशिश ये कर रहे हैं उतना ही अधिक ये पूंजीवादी व्यवस्था और शासकों के ताबेदार बनते जा रहे हैं। इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि इन्होंने चुपचाप शासकों एकाधिकारी पूंजीपतियों और उनकी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जन आन्दोलन के रास्ते से अपने को अलग कर लिया। इसके लिए तर्कों का कोई अभाव नहीं था। दमन है, उदासीनता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कटु सत्य यह है कि इन्होंने जन आन्दोलन का रास्ता त्याग दिया क्योंकि ये अपने आकाओं को दिक्कत या परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं और इस तरह इस विशाल देश को घोर प्रतिक्रियावादियों के लिए खुला छोड़ दिया गया कि वे इस पर धावा बोल सकें और अपना खेल खेल सकें। तथाकथित बड़ी वामपंथी पार्टियों की निष्क्रियता और जी-हुजूरी के रूप में आर.एस.एस.-भाजपा को वरदान मिल गया।

मोदीजी और उनका दो वर्ष का शासन

लेकिन लोगों के लिए यही अंत नहीं है। बेरहम पूंजीवादी शोषण उनकी खाल तक उतारने पर उतारू है। इसलिए असंतोष और आक्रोश बढ़ता ही गया और यह कभी-कभार फूट पड़ने का प्रयास भी करता रहा। इससे भी बढ़कर आर.एस.एस.-भाजपा के हिन्दुत्ववादी एजेण्डे के पसरते खतरे से पैदा तर्कहीनता, असहिष्णुता और साम्प्रदायिकता के मनहूस वातावरण की पृष्ठभूमि से भय और अविश्वास उत्पन्न हो गया था। इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मोदीजी के शासन ने चालाकीपूर्ण रणनीति का सहारा लिया। एक साम्प्रदायिक घटना के भड़कने पर इतने वाचाल प्रधानमंत्री या ता चुप रहते हैं या घाव को और भी गहरा होने देते हैं। केवल उसके बाद ही वे और उनके पार्टी नेताओं का गिरोह सहिष्णुता के लिए पैरवी शुरू करता है जबकि कुछ दूसरे सिलसिला जारी रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विकास का राग भी अलापना शुरू कर दिया है जिस पर सवार होकर एकाधिकारी पूंजीपतियों के चहेते नरेन्द्र मोदीजी सत्तारूढ़ हुए थे। लेकिन मोदीजी की सरपरस्ती में दो साल के भाजपा शासन ने अच्छी तरह दिखा दिया है कि असलियत क्या है।

हर पहलू से विकास का यह वर्णन झूठ, फर्जी सामग्रियों, तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित था जिन्हें कल्पित दावों व नाटकीय अंदाज में चालाकीपूर्वक परोसा गया था जिनकी कलई जल्दी ही खुल गई। मोदी ने लोगों से अच्छे दिनों का वादा किया था। कितने अच्छे दिन आए अपने दो साल के शासनकाल में मोदी ने उनको जो-जो तोहफे दिए हैं इससे वे बखूबी समझ गए हैं। उनके अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने दावा किया है कि मोदी के शासन के दौरान साम्प्रदायिक उपद्रव की घटनाओं की संख्या में कमी आई है। लेकिन संसद में (24 फरवरी 2014) को एक सवाल के जवाब में दिए गए केन्द्रीय सरकार के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर पेश करते हैं। इसने साम्प्रदायिक उपद्रवों में बढ़ोतरी का खुलासा किया है। (2014 में 644 से 2015 में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है) साथ ही साथ साम्प्रदायिक दंगों में मरने वालों और घायलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। (क्रमशः 2014 में 95 से लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि और 2014 में 1921 से 18 प्रतिशत की वृद्धि इसी अवधि के दौरान हुई है।) सितम्बर 2013 में हुए मुजफ्फर नगर दंगों सहित जहाँ जाट हिन्दू और जाट मुसलमान दशकों से मेल मिलाप से रह रहे थे, 50 से अधिक बड़े या छोटे साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं के माध्यम से दिल्ली की गद्दी पर पहुंचे मोदीजी का भव्य स्वागत किया गया था। अब आइए, आर्थिक पक्ष पर गौर करें। सत्तासीन होते ही मोदी सरकार ने रेल किराए और मालभाड़े बढ़ा दिये थे जिसके चलते तमाम वस्तुओं के दामों में चौतरफा वृद्धि हुई। सरकार ने जीवनरक्षक दवाओं तक के दामों को नियंत्रणमुक्त कर दिया, स्वास्थ्य बजट को घटा दिया था और मेडिकल सुविधाओं को भी मुनाफा कमाने की वस्तु घोषित कर दिया जिसने लोगों की मुसीबतें तो बढ़ा दी लेकिन दवा उत्पादक कॉरपोरेट घरानों को अकूत मुनाफा कमाने की सुविधा कर दी। इसने सर्वव्यापक सेवा कर लोगों पर थोप दिया, उन सेवाओं के लिए भी जिसका भुगतान वे पहले ही कर चुके हैं। इसने देश को साफ रखने के लिए स्वच्छ भारत टैक्स भी जोड़ दिया। लेकिन इसने निवेशकों के लिए सम्पत्ति टैक्स को 30 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया। वाह! क्या सुन्दर चुनाव है जरूरतमंद का। औद्योगिक क्षेत्र में सुधारों के जरिए या नए कानून लाकर इसने श्रम कानून को इस कदर तोड़ा-मरोड़ा है कि 90 प्रतिशत संस्थानों (जहाँ 300 से कम वर्कर लगे हैं) के मालिकों को जब चाहे मजदूरों को निकालने का निरंकुश अधिकार मिल गया है और फैक्ट्री एक्ट में ऐसा संशोधन किया गया है जिससे 71 प्रतिशत मजदूर इसके दायरे और सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति लेने को निरस्त कर दिया गया है और सीमित मुआवजा सिर्फ मालिकों को ही दिया जाएगा अन्य किसी को जैसे बटाईदार या खेतीहर मजदूर को नहीं। 100 दिनों का रोजगार प्रोजेक्ट जो यू.पी.ए. सरकार के शासन में पहले से ही दयनीय हालत में घिसट कर चल रहा था, उसको सीमित करने का प्रयास करके इसने ग्रामीण गरीबों के जले पर और नमक छिड़क दिया है। जमीन से बेदखली, ग्रामीण बेरोजगारी और इसकी सहजात दुर्दशा सीमाहीन हो गई है। आदिवासियों की ग्रामसभा के अनुमोदन के बिना ही वन भूमि के अधिग्रहण के लिए कानूनों को सरकार ने उदार बना दिया है जिसके चलते देश के लगभग 21.05 प्रतिशत क्षेत्र के लोग खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन इसे उद्योगपतियों को यह इजाजत देने में कोई हिचक नहीं हुई कि उनको आवंटित भूमि को वे कितने ही लम्बे अर्से तक बिना इस्तेमाल किए पड़ा रख सकते हैं। कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है और न ही सरकारी संस्थानों में निचले स्तर पर नए पदों का सृजन हो रहा है जिसने बेरोजगारी को और भी बढ़ा दिया है।

मोदीजी खुद के बारे में और उसके आर.एस.एस.-भाजपा गठजोड़ के बारे में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा होने का दिखावा करते हैं। अफसोस! मात्र कुछ दिन पहले ही एक वरिष्ठ आर.एस.एस.-भाजपा पदाधिकारी जिसे एक आज्ञाकारी गवर्नर के रूप में दो महत्वपूर्ण नार्थ ईस्ट राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए नियुक्त किया गया था। उस पर यौन प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार के आरोप लगे थे जिससे राजभवन की गरिमा को गहरा आघात पहुंचा था। बेआबरू होकर पद त्याग करने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। खुद मोदीजी ने लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए के बैंक कर्ज की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया है, मुख्यतः इसकी देनदारी बड़े कॉरपोरेट घरानों पर है, यह कर्ज बैंकों के पास नॉन-परफोरमिंग एसैट (बट्टे खाते) के रूप में पड़ा हुआ है, हालांकि मोदीजी कालाधन बाहर निकालने का और भ्रष्टाचार खत्म करने का दंभपूर्ण दावा कर रहे हैं। जबकि मोदीजी और उनकी सरकार ने बीसियों क्षेत्रों के लिए सरकार अनुमोदित रूट के तहत सीधे विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को उदार बना दिया है जिसमें छोटे और मझौले उद्योगों के उत्पादों का थोक व्यापार और सिंगल ब्राण्ड का खुदरा व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री, प्राइवेट बैंकिंग, यहाँ तक कि डिफेंस इत्यादि भी शामिल है। जैसी उम्मीद थी वैसे ही परिणाम हुए और हो रहे हैं। दुनिया में 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट में अब भारत का स्थान 7वां है। सन् 2000 से भारत के सबसे अमीर 10 प्रतिशत धीरे-धीरे और अमीर होते जा रहे हैं और अब कुल धन-सम्पदा का लगभग 75 प्रतिशत उनके पास है और भारत के 1 प्रतिशत धनकुबेर और भी तेजी से अमीर होते जा रहे हैं। इसका ठीक उल्टा भी है, दुनिया में आधुनिक गुलामी के शिकार लोगों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है, जिसमें 183.5 लाख जबरन श्रम यानी बंधुआ मजदूरी का शिकार हैं, इसमें वेश्यावृत्ति से लेकर भिक्षावृत्ति तक शामिल हैं। 77 प्रतिशत भारतीय गरीबी रेखा से नीचे सिसक रहे हैं जिनकी आमदनी प्रतिदिन 20 रुपए भी नहीं है। फिर, आजादी के बाद से जो होता आ रहा है, यह सब पूरी तरह उसी के अनुरूप है। केवल इतना हुआ है कि व्यवस्था के संकट के और भी गहराने की वजह से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी हो गई हैं और लोगों की नजर और दिमाग से इसे छिपाए रखने के लिए किसी भी प्रतिवाद का दमन करने में बेरहमी और दम्भ अपने चरम पर है।

आरएसएस-बीजेपी को पूरी तरह बेनकाब करते हुए सही लाइन पर जन-आन्दोलन है देश की जरूरत

अतः समापन करने के लिए सारांश को एक बार फिर दोहरा देते हैं। जाहिराना तौर पर संसदीय जनतंत्र को उनके द्वारा चलाया जाता है जिन्हें शासक वर्ग अपने भरोसेमन्द राजनीतिक मैनेजर के रूप में चुनता है, लोगों के बीच स्वीकार्य बनाने के लिए उन्हें संवारता है और शासन की बागडोर उनके हाथों में सौंप देता है। यह 'पवित्र' व्यवस्था हालांकि बेसुध, हताश गरीब अपनी आजीविका, अधिकारों और जीने की सामान्य सुरक्षा तक को खोते जा रहे हैं। संसदीय जनतंत्र के इस मुखौटे की आड़ में पूरी की पूरी आर्थिक और राजनैतिक शक्ति शासक वर्ग, एकाधिकारी पूँजीपतियों के हाथों में संकेन्द्रित है। इसी तरीके से चुपचाप प्रशासनिक फासीवादीकरण की ओर यह अग्रसर हो रहा है। इस संदर्भ में इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि हमेशा सैनिक तानाशाही ही फासीवाद नहीं होती है। जनतंत्र का मुखौटा रखते हुए भी फासीवादी अपने षड़यंत्र के पीछे जन समर्थन जुटा लेते हैं और जन मानस को अपने पक्ष में ढाल लेते हैं। शासक वर्ग एकाधिकारी पूँजीपतियों की स्वार्थ सिद्धि के लिए यह दो धारी तलवार काम करती है। एक तरफ आर.एस.एस.-बीजेपी गठजोड़ बल्कि अपने घटकों और सहयोगियों के साथ पूरा संघ परिवार अपनी जहरीली साम्प्रदायिक राजनीति को निरन्तर फैलाता जा रहा है और इसे जन मानस में भरता जा रहा है, जिसका उद्देश्य है अंधविश्वास, तर्कहीन दकियानूसी विचार और चिंतन, तमाम तरह की कट्टरता से जन मानस को पैटर्न करते हुए गैर तार्किक और गैर राजनीतिक मन तैयार करना। दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्वाधीन सरकार विकास के नितांत कपटपूर्ण नारे के जरिए लोगों को धोखा देने, प्रधानमंत्री मोदीजी की वास्तविकता से कहीं बड़ी छवि का निर्माण करने और फिर इस छवि के जरिए उन्हें लुभाने और सम्मोहित करने का जीतोड़ प्रयास कर रही है। सरकार भोली-भाली जनता को उस वध-स्थल की ओर ले जा रही है जिसका निर्माण फासीवादी शासक धूर्ततापूर्वक उनके लिए करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसलिए सभी जनवाद पसन्द लोगों का फर्ज बनता है कि वे बाहर निकलें और इस षड़यंत्र को समझने में जनता की मदद करें। स्थिति का तकाजा है कि पूँजीवादी व्यवस्था और लोगों के अभिव्यक्ति व प्रतिवाद के अधिकार सहित उनके जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाला हर एक मुद्दा जो यह पैदा कर रही

(शेष पृष्ठ 6 पर)

आशा व मिड-डे मील कार्यकर्ताओं ने किया रोष प्रदर्शन

रोहतक (हरियाणा) : 27 फरवरी को आशा कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा एवं मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा सम्बन्धित एआईयूटीयूसी के संयुक्त आह्वान पर प्रदेश भर से आई हजारों आशा व मिड-डे मील कार्यकर्ताओं ने यहां रोष प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त, रोहतक की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि आशा एवं मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाये, तब तक 18000 रुपये मासिक मेहनताना दिया जाये, 5 बच्चों पर एक मिड-डे मील कार्यकर्ता नियुक्त हो, मिड-डे मील के लिए स्कूलों में उचित रसोई एवं पोषक आहार का प्रबंध हो, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को छुट्टियों का मेहनताना दिया जाए, आशा वर्कर को पीएचसी एवं सीएचसी तथा हस्पतालों में आन-जाने के लिए फ्री बस पास व फ्री रेलवे पास दिया जाये, आशा व मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा दी जाए, बीमारी में नि:शुल्क ईलाज एवं दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 11 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए और महिलाओं पर बढ़ते अपराध की रोकथाम हो।

रोहतक : मांगों के लिए सड़कों पर उतरी स्कीम वर्कर

इस रोष प्रदर्शन का नेतृत्व आशा कार्यकर्ता यूनियन एवं मिड-डे कार्यकर्ता यूनियन की रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार, जीन्द, कैथल, पानीपत, गुड़गांव आदि जिलों से आई नेत्रियों सुषमा यादव, राजबाला यादव, ओमवती, सीमा, रेखा, मुनेश, मीरा देवी, बिमला, नरकेश, सन्तोष, कृष्णा, मुन्नी, निर्मला, इन्द्रा, कलावती, मन्जू, मूर्ति व विद्या देवी ने किया। प्रदर्शन को एआईयूटीयूसी के प्रदेश प्रधान कॉमरेड सत्यवान व कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने भी सम्बोधित किया।

राज्य स्तरीय यूथ समिट का आयोजन

इन्दौर: यूथ समिट को सम्बोधित करते हुए कॉ. जुबैर रब्बानी

इन्दौर (म.प्र.) : 19 फरवरी 2017 को मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) द्वारा एक राज्य स्तरीय यूथ समिट का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से डीवाईओ के कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले पूरे प्रदेश भर में दो माह तक लगातार प्रचार अभियान चलाया गया। इसमें- इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, गुना, अशोक नगर, सागर, शिवपुरी, देवास, रायसेन, आरोन, मण्डीदीप, औबेदुल्लागंज में जगह-जगह चौराहों पर, गली-मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं की गई। बेरोजगारी, अश्लीलता, अपसंस्कृति, शराबखोरी के खिलाफ तथा सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। दीवार लेखन तथा पोस्टरिंग के माध्यम से प्रदेश भर में आंदोलन को तेज करने के लिए प्रचार किया गया।

यूथ सम्मिट में इन्दौर के जाने माने वरिष्ठ नागरिक, म.प्र. के पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार देशी-विदेशी उद्योगपतियों-पूंजीपतियों को बुलाकर अत्यधिक मुनाफा लूटने के लिए इन्दौर में इन्वेस्टर्स मीट करती है, तो ये नौजवान भी रोजगार की मांग के लिए यूथ समिट कर रहे हैं-इन्हें पूरा हक है। उन्होंने नौजवानों से इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़कर समाजवाद लाने की अपील की।

इन्दौर हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट व जानेमाने समाजसेवी अनिल त्रिवेदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का आंदोलन घर-घर में चलना चाहिए। जब किसी माँ-बहन का पति, भाई या बेटा नशे की हालत में शराब पीकर घर आयेगा तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। कम से कम यहां उपस्थित माँ-बहनें यह आंदोलन अपने घर में चलाएं और जब छात्र, नौजवान, माताएं-बहनें शराबबंदी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगी तो आंदोलन के दबाव में शराबबंदी करने के लिए सरकार मजबूर हो जायेगी।

कार्यक्रम में मुख्यवक्ता के रूप में बोलते हुए एआईडीवाईओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कां. जुबेर रब्बानी ने कहा कि बेरोजगारी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के साथ-साथ म.प्र. में भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कई पार्टियों की सरकारें सत्ता में आयी लेकिन किसी ने भी रोजगार देने की नीति नहीं बनायी। जहां एक तरफ करोड़ों करोड़ बेरोजगार हैं वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को सरकार बंद कर रही है, कारखाने लगातार बंद हो रहे है और जो भी काम दिया जा रहा है वह भी ठेके पर। ठेके का रोजगार कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज म.प्र. के नौजवान रोजगार की मांग को लेकर यह यूथ समिट कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों युवा म.प्र. के कई जिलों से आये हैं। कॉमरेड रब्बानी ने शराबबंदी, अश्लील वेबसाइट और अश्लील सिनेमा के प्रचार को रोकने पर भी जोर दिया तथा म.प्र. में युवा आंदोलन को तेज करने की अपील की।

यूथ सम्मिट में शराबखोरी, अश्लीलता, अपसंस्कृति, बेरोजगारी के खिलाफ व सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग पर आंदोलन तेज करने के लिए एक प्रस्ताव संगठन की राज्य सांगठनिक समिति के सदस्य कां. अजय श्रीवास्तव के द्वारा पेश किया गया, जिसके समर्थन में संगठन की राज्य सांगठनिक समिति के सदस्य कां. सिद्धान्त साहू, कां. निहार सोनी तथा गुना नगर कमेटी सचिव कां. नीरज बैरागी ने अपनी बात रखी तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पहले यूथ सम्मिट में संगठन की प्रदेश सह संयोजिका कां. प्रतिज्ञा मांझी ने अपने उद्घाटन उद्बोधन में युवा आंदोलन की जरूरत पर प्रकाश डाला। सर्वहारा वर्ग की पार्टी एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के राज्य सांगठनिक सदस्य कां. प्रदीप आर.बी. ने सभी को क्रान्तिकारी बधाई दी। मंच पर एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) की इन्दौर प्रभारी कां. अर्शी खान भी उपस्थित थी।

कार्यक्रम के अंत में इन्दौर के निशान ग्रुप द्वारा अशोक चक्रधर की प्रसिद्ध रचना ''दो कटे हाथ'' का मंचन किया गया जिसे उपस्थित सभी लोगों ने बहुत सराहा। यूथ समिट की अध्यक्षता एआईडीवाई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा म.प्र. संयोजक कां. लोकेश शर्मा ने की एवं संचालन एआईडीवाईओ के राज्य सांगठनिक समिति सदस्य तथा इन्दौर प्रभारी कां. प्रमोद नामदेव ने किया।

नोटबंदी के दुष्परिणामों पर वामदलों ने किया मंथन

गुना (म.प्र.) : नोटबंदी के खिलाफ यहां वामपंथी पार्टियों की ओर से 7 फरवरी को होटल सम्राट में संयुक्त सभा हुई। इसमें सीपीआई, सीपीआई(एम) व एसयूसीआई(सी) के कार्यकर्ता काफी संख्या में शामिल हुए। सभा में नोटबंदी-आर्थिक मंदी और उसके दुष्परिणामों पर चर्चा हुई। एसयूसीआई(सी), गुना जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड संगीता आर बी और अख्तर खान, सीपीएम से कॉ. विष्णु शर्मा और सीपीआई से कॉ. अमानत अली व अजीत जैन ने सभा को सम्बोधित किया।

बैंक द्वारा किसानों के खातों से बीमे का पैसा जबरन काट लेने का विरोध

आरोन (म.प्र.) : एसबीआई द्वारा किसानों के खातों से मौसम की जानकारी व दुर्घटना बीमा के नाम से काटे जा रहे रुपयों के विरोध में और किसान क्रेडिट कार्ड भरने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी को बढ़ाये जाने की मांग को लेकर ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) आरोन इकाई द्वारा गत दिनों एक ज्ञापन माननीय अनुविभागीय अधिकारी नीरज शर्मा को सौंपा गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान शामिल हुए। संगठन के प्रभारी कॉ. मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में किसान और किसानी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा और सरकार बड़ी-बड़ी कम्पनियों को खेती में आने की मंजूरी दे रही है। ऐसे में बैंकों का यह रवैया घोर किसान-विरोधी है। इसके बावजूद भाजपा के मंत्री व विधायक किसानों पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।

ज्ञापन में मांग की गई कि किसानों के खातों से बैंक बिना उसकी मर्जी के रुपये काटना बंद करे और काटे गये रुपयों को पुन: उसके खातों में स्थनान्तरित किया जाये, किसान कार्ड की राशि जमा करने की तिथि बढ़ाई जाये और किसान को ब्याज मुक्त किया जाये, 2016 की बीमा राशि शीघ्रातिशीघ्र किसानों को उपलब्ध कराई जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर की गई करोड़ों रुपये की ठगी की जांच की जाये और किसानों को बीमा राशि दिलवाई जाये, विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा दिये गये अभद्र बयान पर विधायक किसानों से माफी मांगे।

उक्त मांगों को न माने जाने की दशा में किसानों ने आन्दोलन तेज करने की चेतावनी दी।

फीस बढ़ोतरी का विरोध

झारखण्ड की कोल्हान यूनिवर्सिटी में पीजी की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ और उपयुक्त व्यवस्था किये बिना सेमेस्टर सिस्टम व सीबीसीएस लागू करने की घोषणा के खिलाफ एआईडीएसओ ने गत दिनों विभिन्न कालेजों में धरना-प्रदर्शन कर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपे। इसमे यूनिवर्सिटी कॉलेज जमशेदपुर, घाटशिला कॉलेज, टाटा कॉलेज चाईबासा, सिंहभूम कॉलेज चंडिल, काशिसाव कॉलेज आदि शामिल थे।

रांची (झारखण्ड) : छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर 18 फरवरी को ऑल इण्डिया डीएसओ, रांची कमेटी के रामलखन सिंह यादव के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा गया।

कार्यक्रम में कॉलेज कमेटी के अध्यक्ष जुलियस फूचिक के अलावा सरवन सानू, सोनी व अन्य कई छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कॉलेज के विभिन्न समस्याओं को लेकर कॉलेज के 180 छात्रों के हस्ताक्षरयुक्त एक आवेदन भी कुलपति को सौंपा गया।

6 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

सर्वहारा दृष्टिकोण

8 मार्च से 22 मार्च 2017

ब्लॉक स्तरीय युवा सम्मेलन सम्पन्न

भिवानी (हरियाणा) : 23 फरवरी को स्थानीय नेहरू पार्क भिवानी में बेरोजगारी, नशाखोरी, अश्लीलता, कुसंस्कृति और साम्प्रदायिकता के खिलाफ युवा संगठन एआईडीवाईओ का भिवानी ब्लाक का युवा सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता राजेश तिगड़ाना ने की। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के जिला सचिव कॉ. रामफल मुख्य वक्ता थे। संचालन एआईडीवाईओ के जिला सचिव कॉ. संदीप मेहरा ने किया।

मुख्य वक्ता रामफल ने युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी, सांस्कृतिक और नैतिक पतन बढ़ रहा है। शिक्षित और सक्षम होते हुए भी लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। उनका भविष्य आज अंधकारमय है। वे निराश-हताश हो रहे हैं, सामाजिक उत्तदायित्व के प्रति वे उदासीन हैं। प्रचार-प्रसार के साधनों से लगातर अश्लीलता और गंदगी परोसी जा रही है। शराब की दुकाने धड़ाधड़ खोली जा रही हैं। नौजवानों में नशाखोरी की बुरी लत बढ़ती जा रही है। जनता, खासकर नौजवान सांस्कृतिक पतन के शिकार हो रहे हैं। अंधविश्वासों, साम्प्रदायिकता व जातपात को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब मूल समस्याओं का कारण संकटग्रस्त पूँजीवाद है। उन्होंने युवा जीवन की समस्याओं को लेकर जोरदार युवा आन्दोलन गठित करने और उसे पूँजीवाद-विरोधी दिशा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हर युग में सामाजिक परिवर्तन में नौजवानों की अहम भूमिका रही है। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है और युवा जीवन उसका सुनहरा काल है। यही वह दौर है जिसमें मनुष्य में नयी रचना करने की शक्ति होती है। इसके लिए उसे युगोपयोगी नये विचारों, नयी संस्कृति, नये मूल्यबोधों और मेधा शक्ति से लैस होने की जरूरत होती है। वर्तमान में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतनधारा ही नौजवानों की राह रोशन कर सकती है। उन्होंने इसे जीवन-दर्शन के रूप में अपनाने का आह्वान किया।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष राजेश तिगड़ाना, सचिव पवन भिवानी, कोषाध्यक्ष विशाल जांगड़ा और 8 कमेटी के सदस्य चुने गये।

भिवानी: ब्लॉक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉ. रामफल

गुड़गाँव : 19 फरवरी को एआईडीवाईओ, गुड़गाँव ब्लाक का सम्मेलन कीर्ति मोन्टेसरी स्कूल, लक्ष्मण बिहार-प्प में किया गया। सम्मेलन का संचालन जिला सचिव राजेश कुमार ने किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता कॉमरेड बलवान सिंह थे। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य खजान सिंह राठी रहे। सम्मेलन का मूल प्रस्ताव वजीर सिंह ने रखा जिसके समर्थन में एआईयूटीयूसी जिला सचिव कॉ. रामकुमार ने बात रखी। सैक्टर-5 स्थित हुडा ग्राउण्ड के नाम को 'शहीद चन्द्रशेखर आजाद मैदान' रखने का प्रस्ताव राजेश कुमार ने पेश किया। इसका समर्थन सुरेन्द्र शर्मा ने किया। दोनों प्रस्तावों को चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पास किया गया।

अंत में ब्लाक गुड़गांव की कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए वजीर सिंह, सचिव कमलकान्त कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, महेश राणा, योगेश कटारिया, जयन्त कुमार, जसमेर सिंह व राहुल कुमार को सदस्य पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया।

आंगनवाड़ी कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन

सोनीपत (हरियाणा) में 25 फरवरी को राज्य सरकार में मंत्री कविता जैन के आवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने जाती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन रजि. नं. 1996 के बैनर तले जुटी सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं

ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन

कैरू, जिला भिवानी (हरियाणा) : 23 फरवरी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा रजि. नं. 1996 सम्बन्धित एआईयूटीयूसी ने यहां विभागीय अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाये, तब तक 18000 रुपये व 9000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन दिया जाये, रिटायर होने पर 5 लाख एकमुश्त सहायता राशि और 3000 रुपये मासिक पेन्शन दी जाए, इसके अलावा विभागीय पदोन्नति व समायोजन के स्पष्ट नियम बनाने और विभागीय शोषण-उत्पीड़न बंद करने, आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने के साफ पानी, बिजली, पंखा व शौचालय का इन्तजाम करने, आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया हर महीने शहर में 3000 रुपये और गांवों में 1500 रुपये देने की भी मांग की गई।

यूनियन की ब्लॉक सचिव राजबाला ढाब ढाणी, ब्लॉक प्रधान सुशीला खापड़वास के अलावा एआईयूटीयूसी के जिला कमेटी सदस्य कॉ. राजकुमार बासिया ने सम्बोधित किया। आंगनवाड़ी नेत्रियों ने कहा कि मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी स्कीम के लिए न तो बजट आवंटन बढ़ाया और न ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय भत्ते में एक भी रुपया बढ़ाया। प्रदेश सरकार ने जो बढ़ोतरी की है वह महंगाई की तुलना में बहुत कम है। सहायिकाओं के मानदेय भत्ते में विसंगतियां हैं। उन्हें हर महीना 286 रुपये कम दिये जा रहे हैं।

उ.प्र. विधानसभा चुनावों में एसयूसीआइ(सी) द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवार

विधानसभा क्षेत्र	जिला	नाम
मुरादाबाद शहर	मुरादाबाद	कॉमरेड हरिकिशोर सिंह
लम्भुआ	सुलतानपुर	कॉमरेड जयप्रकाश मौर्य
कल्याणपुर	कानपुर	कॉमरेड धर्मदेव
पट्टी	प्रतापगढ़	कॉमरेड रामसमुझ मौर्य
रानीगंज	प्रतापगढ़	कॉमरेड पारसनाथ विश्वकर्मा
बेल्थरा रोड़	बलिया	कॉमरेड शैलेन्द्र राव
बदलापुर	जौनपुर	कॉमरेड जसनारायण मौर्य
मल्हानी	जौनपुर	कॉमरेड प्रवीण कुमार शुक्ला

पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाओं की जारी है मुहिम

दुर्ग (छ.ग.) : शराब भट्ठी के लिए भूमि पूजन की प्रशासनिक कोशिश के खिलाफ 500 महिलाओं ने डिप्टी कलैक्टर को ज्ञापन सौंप कर शराबबंदी की मांग की। 2 मार्च को भट्ठी के लिए खुदाई किये जाने की जानकारी मिलते ही महिलाएं वहां जा पहुंची। कॉ. विश्वजीत हारोड़े व देवेन्द्र पाटिल ने महिलाओं सें बात की। तभी पुलिस वहां गई और उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठा कर दोनों को हथकड़ी लगाकर वहां की पुलिस चौकी में ले गई। उन पर 3 फर्जी धाराएं लगाई गई जिनमें एसडीएम के समक्ष पेश होना पड़ता है। शाम को वे 50-50 हजार रुपये की जमानत पर छूटे।

यह घटना जेवरा सिरसा शराब की दुकान के खिलाफ आन्दोलनकारियों को गैर लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर अनापशनाप धाराओं में फंसा कर आन्दोलन का दमन करने का दमनचक्र है। इससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। महिलाओं ने पुलिस की इस नाजायज कार्रवाई का विरोध किया। पहले भी 15 फरवरी को महिलाओं ने ज्ञापन सौंकर शराबबंदी लागू करने की मांग की थी। कई दिन से शराब-विरोधी मुहिम जारी है।

दुर्ग में ही 13 फरवरी को एसयूसीआई(सी) जिला दुर्ग के नेतृत्व में डिपरा पारा वार्ड 39 तालाब पार मोहल्ले में व्याप्त पीने के पानी व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रदर्शन के साथ ही माननीय कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि डिपरा पारा वार्ड 39 तालाब पार में पीने के पानी की मोटी पाइप बिछायी जाए, घरों में सरकारी नल दिया जाए, सार्वजनिक नलों की संख्या बढ़ायी जाए, नाली निर्माण करायी जाएं, सीवेज के पानी के निकासी की व्यवस्था की जाए।

फासीवादीकरण के कदमों की आहट

(पृष्ठ 4 का शेष)

साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि वाले मोदीजी को 'विकास पुरुष' के रूप में किया गया पेश

है उसके खिलाफ और एक सुन्दर जीवन जीने के लिए एक दीर्घ स्थाई जन आन्दोलन का निर्माण किया जाए। ऐसा एक आन्दोलन सही नेतृत्व के बिना संचालित नहीं किया जा सकता है। ऐसा एक नेतृत्व जो क्रान्ति के धक्के से लोगों को तमाम तरह के शोषण और दमन से मुक्त करने के बारे में संघर्षरत है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आज केवल एसयूसीआई(सी) पार्टी ही है जो इस मिशन को लेकर चल रही है। साथ ही साथ आर.एस.एस.-बीजेपी गठजोड़ की घृणित साम्प्रदायिक राजनीति के पीछे छिपे जहर को भी सही-सही समझना बहुत जरूरी है। इसके हर पहलू को पूरी तरह बेनकाब करने की जरूरत है नहीं तो यह सिर्फ जीवन को ही नहीं बल्कि मानव जाति को खतरे में डाल देगा। एकमात्र एसयूसीआई(सी) ही है जो आरएसएस-बीजेपी खतरे का निरन्तर पर्दाफाश करने में लगी हुई है। इस प्रकार भारत के लोगों के सामने दो लक्ष्यों को पाने की कठिन घड़ी है एक खतरे को सही-सही पहचानना और दूसरा उनके संघर्ष का सच्चा साथी कौन है।

शैक्षणिक समस्याओं के खिलाफ छात्रों ने मनाया विरोध दिवस

ग्वालियर (म.प्र.) : म.प्र. में ऑल इंडिया डी.एस.ओ. द्वारा 17 फरवरी को राज्यव्यापी मांग दिवस मनाया गया जिसमें राज्य शासन से हर स्तर से सेमेस्टर प्रणाली को खत्म करने, कक्षा 1 से 8 तक पास -फेल प्रणाली को लागू करने, क्लोजर व मर्जर नीति के तहत सरकारी स्कूलों को बन्द करने की नीति को वापस लेने तथा स्थायी शिक्षकों की मांग की गई।

ग्वालियर शहर में इस कार्यक्रम की जानकारी गत 14 फरवरी को ऑल इंडिया डी.एस.ओ. के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में दी जा रही थी, तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा तमीज की तमाम हदें पार कर ऑल इंडिया डी एस ओ की न केवल स्टाल को फेंका गया बल्कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी अभद्रता, गाली-गलौज एवं धक्का-मुक्की की गई और समस्त प्रचार सामग्री जिसमें शहीदों, मनीषियों का साहित्य भी मौजूद था, फाड़कर फेंका गया। साथ ही 17 फरवरी को होनेवाले आंदोलन को विश्वविद्यालय में न होने देने की धमकी ए.बी.वी.पी. के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई। इसके जबाव में ऑल इंडिया डीएसओ ने हजारों अपील छापकर आम छात्रों के बीच वितरित की। छात्रों से अपील की गई कि वे शिक्षा, संस्कृति व इन्सानियत को बचाने की लड़ाई में शरीक हों, स्कूल-कॉलेज से निकल कर गुण्डा राज के खिलाफ लामबन्द हों।

17 फरवरी को तमाम बाधाओं के बावजूद सैकड़ों छात्र स्कूल-कॉलेजों से निकलकर हाथों में मांग लिखी तख्तियॉ लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी स्थानीय समस्याओं को हल करने की मांग की तथा राज्य सरकार संबंधित मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने की अपील की। इस तरह इसके साथ ही म.प्र. के अन्य प्रमुख शहरों सहित राजधानी भोपाल में इन्हीं मांगों को लेकर हमीदिया कॉलेज में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया जिसे विनोद लोगारिया ने सम्बोधित किया। इसमें पारूल शर्मा, गब्बर आदि शामिल रहे। देवास में प्रदर्शन कर सेमेस्टर को खत्म करने की अपील की गई। इसे राज्य सचिवमण्डल सदस्य बबिता समर ने सम्बोधित किया। सागर में रवीन्द्र भवन चौराहे पर प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसे कृष्णा वैरागी द्वारा सम्बोधित किया गया और वीरेन्द्र साहू, तेजवान साहू, अरविन्द पटेल आदि शामिल रहे।

श्रमिक अधिकार दिवस पर रैली...

(पृष्ठ 1 का शेष)

सभी यूनियनों के वक्ताओं ने केन्द्र व राज्य सरकारों पर आरोप लगाया कि लम्बे समय से उनकी मांगें लम्बित है, लेकिन सरकारें उनके समाधान की ओर कोई तवज्जो नहीं दे रही हैं। आंगनवाड़ी, आशा व मिड डे मील वर्करों ने सरकारी कर्मचारी मानने और पी.एफ, पेन्शन सहित उन्हें पूरा वेतन व अन्य हितलाभ देने की मांग की। उन्होंने पी.एफ में की गई ब्याज कटौती वापस लेने, हरेक सरकारी क्षेत्र में अवमूल्यन, निजीकरण, निगमीकरण, ठेकाकरण, पीपीपी, कर्मचारियों की संख्या में कटौती व आउटसोर्सिंग बंद करने की भी मांग की। भवन निर्माण कर्मियों ने सभी तरह की सहायता राशि बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग की। इसके अलावा नोटबंदी से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए भी अपनी आवाज बुलंद की।

उपराज्यपाल आवास पर पहुंचकर यह जुलूस एक विरोध सभा में तब्दील हो गया। जहां कार्यक्रम का संचालन किया कॉ. एन. के. रावत ने। सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. रमेश शर्मा ने कहा कि इस प्रतिगामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में मेहनतकश जनता को अपने जायज व कानूनी हकों को भी संघर्ष से ही हासिल करना पड़ेगा। सभा को आशाओं की ओर से दिल्ली राज्य महासचिव शिक्षा राणा, उपाध्यक्ष-ममता राव, सचिव कविता व शीला सुजाता ने, आंगनबाड़ी की ओर से-कॉ. रामकरण व मीना ने, कॉ. निर्मल कुमार, राकेश, भरतवीर, राजीव, सुदेश, ममता राव ने सम्बोधित किया।

मध्यप्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की उठी मांग

मनाया गया राज्यस्तरीय विरोध दिवस

भोपाल : पूर्ण शराबबंदी की मांग पर धरना-प्रदर्शन करते हुए महिलाएं

भोपाल (म.प्र.) : महिलाओं व बच्चियों पर दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। नशा व अश्लीलता इसके बड़े कारण हैं। इसलिए शराबबंदी लागू होना अत्यावश्यक है। महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराधों, अश्लीलता, अपसंस्कृति पर रोक लगाने और म.प्र. में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर संगठन पूरे प्रदेश में धरना, जुलूस, प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। संगठन की भोपाल इकाई के परचम तले 20 फरवरी को यहां आनंदनगर के चौराहे से महिलाओं द्वारा जुलूस निकाला गया, ज़ोरदार नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने रोष प्रदर्शन किया। ऑल इण्डिया एम.एस.एस की म.प्र अध्यक्षा श्रीमति जॉली सरकार द्वारा बात रखी गई। आरती ने जुलूस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सभा का संचालन ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की सदस्य आरती शर्मा ने किया।

मण्डीदीप : यहां बाजार के मुख्य चौराहे पर एकत्रित होकर महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इसका नेतृत्व मण्डीदीप प्रभारी रितु श्रीवास्तव, एम.एस.एस की राज्य कार्यालय सचिव श्रीमति सुनिधि चौहान द्वारा किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में शराबबंदी की मॉग की। शर्मिला सहित तमाम महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

गुना : आरोन सहित शहर के अलग-अलग हिस्सों से आई महिलाओं द्वारा शराबबंदी की मांग पर हनुमान चौराहे पर 19 फरवरी को धरना दिया गया।

धरने को मुख्य रूप से ऑल इण्डिया एम.एस.एस की राज्य सचिव मण्डल सदस्या प्रीति पटवर्धन, गुना जिला अध्यक्ष संगीता आर.बी., गुना जिला सचिव निधि श्रीवास्तव ने संबोधित किया। म.प्र. सरकार द्वारा शराब को बढ़ावा देने की नीति का कड़ा विरोध जताते हुए नशे के कारण गरीब परिवारों की बदहाली और महिलाओं पर अपराधों में बढोतरी पर वक्ताओं ने रोष और चिंता जताई और सरकार से पूर्ण शराबबंदी की मांग की।

धरने में सीमा राय, दीपिका वर्मा, निहारिका ने भी बात रखी। एस.यू.सी.आई.(सी) की ओर से कॉ. मनीश श्रीवास्तव ने धरने को संबोधित किया।

ग्वालियर : यहां फूलबाग चौराहे पर जीवाजीगंज, अवाड़पूरा, गोशपुरा, रानीपूरा, चंद्रवदनी नाका आदि स्थानों से आई महिलाओं ने शराबबंदी की मांग पर 20 फरवरी को धरना दिया। धरने में मुख्य रूप से ऑल इण्डिया एम.एस.एस की राज्य सचिव रचना अग्रवाल ग्वालियर जिला अध्यक्ष आभा भूवरकर, ग्वालियर जिला उपाध्यक्ष मनस्वी राठौरिया द्वारा बात रखी गई। सभी वक्ताओं अनीता पाराशर, त्रिवेणी, सीमा, कमलेश और रागिनी ने शराबबंदी की मांग की। धरने का संचालन भूमिका द्वारा किया गया।

देवास : यहां सायाजी गेट पर महिलाओं व छात्रओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। व अश्लीलता पर रोक व शराबबंदी की मांग की गई। देवास की ऑल इण्डिया एम.एस.एस प्रभारी वाणी जाधव द्वारा वक्तव्य दिया गया। संध्या द्वारा भी शराबबंदी के समर्थन में बात रखी गई।

प्रदर्शन को एस.यू.सी.आई.(सी) के देवास प्रभारी हिमांशु श्रीवास्तव द्वारा संबोधित किया गया। जुलूस के रूप में अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। शबनम, मंजू, शीतल, मनीषा, मोनिका भी उपस्थित रहे।

अशोकनगर : अशोकनगर के अंबडेकर पार्क चौराहे पर एम.एस.एस के बैनर तले जुटी छात्राओं व महिलाओं द्वारा पूर्ण शराबबंदी की मांग की गई। वक्ता के रूप में संगठन की गुना जिला अध्यक्ष संगीता आर.बी. उपस्थित रही। संचालन पुष्पा द्वारा किया गया। नशा व अश्लीलता की लगातार बढ़ोतरी से महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे है अत: शराबबंदी के समर्थन में जोरदार आन्दोलन गठित करने की अपील की गई।

अन्य विवरण फॉर्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन का स्थान	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशन की अवधि	: पाक्षिक
मुद्रक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सम्पादक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
उन व्यक्तियों के नाम एवं पते जो अखबार के स्वामी हैं या जो कुल पूँजी के एक प्रतिशत या उससे अधिक के हिस्सेदार हैं	: सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इंडिया(कम्युनिस्ट)

मैं सत्यवान, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि दिए गए उपरोक्त विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य हैं।

ह. सत्यवान

दिनांक : 5 मार्च, 2017 प्रकाशक के हस्ताक्षर

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Publication : March 5, 2017

सर्वहारा दृष्टिकोण

8 मार्च से 22 मार्च 2017

रामजस कॉलेज से निकले शांतिपूर्ण जुलूस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के कायराना हमले की एआईडीएसओ ने की कड़ी निंदा

ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के महासचिव कॉ. अशोक मिश्रा ने 28 फरवरी को जारी एक बयान में कहा :

21 फरवरी को रामजस कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गुण्डागर्दी के विरोध में 22 फरवरी को दिल्ली में रामजस कॉलेज से मौरिश नगर पुलिस थाने तक निकले शांतिपूर्ण जुलूस पर एबीवीपी गुण्डों के कायराना हमले की एआईडीएसओ कड़ी निंदा करता है; सैकड़ों पुलिसियों की मौजूदगी में आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी ने रामजस कॉलेज में 'कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट' विषय पर सेमिनार के आयोजकों पर हमला किया, उनको सभागार के अन्दर ताला लगाकर बंद कर दिया और उन पर पत्थर फेंके। 22 फरवरी को एबीवीपी की इस गुण्डागर्दी का विरोध करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पर जमा हुए छात्र-शिक्षकों पर पुलिस की मदद से बेरहमी से हमला किया गया। एबीवीपी के गुण्डों ने महिला प्रदर्शनकारियों तक के कपड़े फाड़ दिये, उनसे छेड़छाड़ की और शिक्षकों को पीटा। इस घटना के बाद गुरमेहर कौर ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के एक अंग के तौर पर उन्होंने कुछ प्रोफाइल पिक्चरें पोस्ट की जिनमें उसने अंग्रेजी में लिखे प्लेकार्ड दिखाये : ''मैं एबीवीपी से नहीं डरती''। यह अभियान वायरल हो गया और देश भर से छात्र उनके साथ जुड़ गये। कारगिल युद्ध में जान कुर्बान करने वाले एक फौजी की बेटी की आवाज को दबाने के लिए उसे बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी दी गई। उस पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगाने का अभियान भी छेड़ दिया गया जिसने आरएसएस-बीजेपी के संगठनों के दोहरे मानदण्ड और असली चरित्र को बेनकाब कर दिया। दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने की बजाय, एक बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने तो गुरमेहर की तुलना कुख्यात अण्डरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कर डाली। केन्दीय मंत्री किरन रिजिजू ने यह सुझाव देने का ट्वीट करके एबीवीपी के कुकृत्य का समर्थन किया कि वह किसी व्यक्ति या ग्रुप द्वारा प्रभावित की जा रही है।

एआईडीएसओ का मानना है कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करने के लिए और शिक्षण संस्थानों में जनतांत्रिक स्थान को संकुचित करने के लिए संघ परिवार की छात्र शाखा एबीवीपी देश भर में इस तरह के हमलों को अंजाम दे रही है। रोहित वेमुला की मौत और जेएनयू से नजीब के गायब हो जाने की घटनाएं विरोधियों पर हमलों की मुंह बोलती मिसाल है। इससे पहले भगवां ब्रिगेड ने हैदराबाद की एचसीयू, ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली की जेएनयू, पुणे की एफटीआईआई, हरियाणा की सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी, जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी और दूसरी जगह कैम्पस का जनतंत्र खत्म करने की कोशिश की थी। एबीवीपी गुण्डों ने किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली में एक फिल्म की स्क्रीनिंग में गड़बड़ी फैलाई थी; खालसा कॉलेज, दिल्ली में नुक्कड़ नाटक रद्द करवा दिया था; दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फेकल्टी में हो रही एक जनसभा पर हमला किया था; यौन उत्पीड़न के खिलाफ छात्राओं के जुलूस पर हमला किया था। देश भर में वामपंथियों और अन्य प्रगतिशील व जनतांत्रिक ताकतों का बढ़ता सुदृढ़ीकरण मुख्य रूप से उनके निशाने पर है। साफ जाहिर है कि आरएसएस-बीजेपी से सम्बद्ध एबीवीपी और अन्य संगठनों द्वारा बरपायी गई हिंसा को पुलिस-प्रशासन के अप्रत्यक्ष समर्थन के जरिये राज्य की शह मिली हुई है।

सभी जनतांत्रिक विचारों वाले छात्रों, शिक्षकों और समाज के व्यापक तबकों से कॉमरेड अशोक मिश्रा ने अपील की कि संघ परिवार द्वारा किये जा रहे इन फासीवादी हमलों के खिलाफ आगे आयें, कैम्पस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए व विरोध की आवाज की रक्षा करने के लिए जोरदार आन्दोलन गठित करें और शिक्षा, संस्कृत और इन्सानियत पर हो रहे हमले के खिलाफ एकजुट हों।

झारखंड सरकार द्वारा सीएनटी-एसपीटी एक्ट में किये गये संशोधन के संबंध में
वामदलों ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

कोल्हान (झारखण्ड) : झारखण्ड के चार वाम दलों सीपीआई, सीपीआई(एम),एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), भाकपा(माले) द्वारा 16 फरवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड में सत्तासीन सरकार द्वारा हाल ही में लिये गये कुछ निर्णय से झारखंडवासी अत्यंत दुखी, हताश व साथ ही आक्रोशित भी है। कई हजार सालों से रह रहे इस देश के आदिवासियों को जमीन से बेदखल, विस्थापित कर उन पर जुल्म ढाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए इस धरती के वीर नायक सिदो-कान्हू, बीरसा मुंडा की कुर्बानी के बदौलत ब्रिटिश जमाने में सीएनटी-एसपीटी एक्ट बना था। यह एक्ट हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। इस कानून के साथ झारखंड के गरीब आदिवासी जनता का हित, भावना व आवेग जुड़ा हुआ है। पर कॉर्पोरेट पूंजी व भू माफियाओं के हित में विगत शीतकालीन सत्र के दौरान झारखंड सरकार के द्वारा इस एक्ट में संशोधन से संबंधित बिल विधानसभा में संख्या बल के आधार पर बिना किसी बहस के मात्र 3 मिनट में पास कराया गया। यह सम्पूर्ण रूप से गैर लोकतांत्रिक कदम है। इस तरह के कदम उठाने से पहले राज्य के शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, विभिन्न आदिवासी जनसंगठन, अन्य राजनैतिक दल-किसी से भी कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। इससे झारखंड में भयावह और संकट पूर्ण परिस्थिति तैयार हो रही है। सभी विपक्षी राजनैतिक दल व विभिन्न जनसंगठन एकजुट होकर इस संशोधन के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। लगातार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन और साथ ही साथ पुलिसिया दमन भी चल रहा है। यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध का स्वर उठ रहा है। इसी बीच झारखंड में मोमेन्टम ग्लोबल समिट आयोजित कर विभिन्न देशी-विदेशी पूंजीपतियों को जल-जंगल-जमीन की लूट के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

कुल मिलाकर स्थिति विस्फोटक है। कभी भी कोई बड़ी हिंसक घटना घटित हो सकती है। इस स्थिति में हम सभी वामपंथी दल आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस बिल को अविलम्ब प्रभाव से निरस्त करें और इस विषय पर तानाशाही के बजाए बहस, विमर्श व व्यापक सहमति बनाने के लिए सरकार को प्रेरित करें।

कन्वेन्शन को एआईडीवाईओ के प्रदेश संयोजक लोकेश शर्मा, एआईडीएसओ. के प्रदेशाध्यक्ष मुदित भटनागर, समाजसेवी राजेन्द्र तिवारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एआईएमएसएस की प्रदेशाध्यक्ष जॉली सरकार ने की।

मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू कराने के लिए कन्वेन्शन आयोजित

भोपाल : कन्वेन्शन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड प्रताप सामल

भोपाल (म.प्र.) : महिलाओं, बच्चियों पर बढ़ते अपराध, अश्लीलता व अपसंस्कृति, बेरोजगारी, शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण-सांप्रदायीकरण के खिलाफ व म.प्र. में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर हिंदी भवन में कन्वेन्शन हुआ। कन्वेन्शन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता कॉ. प्रताप सामल, राज्य सचिव एस. यू.सी.आई.(सी) ने कहा कि आज म.प्र. महिलाओं व बच्चियों के लिये सबसे असुरक्षित राज्यों में शामिल है। 2015 के नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार म.प्र. में महिलाओं पर सबसे अधिक अपराध हुए हैं। इसको रुकवाने के लिये शराबबंदी लागू होना निहायत आवश्यक है। सरकार नर्मदा किनारे तो शराब के ठेके बंद करने की घोषणा कर रही है और मुख्यमंत्री नर्मदा किनारे के गांवों के नौजवानों को तो शराब न पीने का उपदेश देते हैं, पर खुद पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। शराब बिक्री का समय बढ़ा दिया गया है। पिछले दिनों नोटबंदी के दौरान कई लोगों की नौकरी छिन गई। प्रदेश में कई लाख पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में 4000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बिना शिक्षक के चल रहे हैं, वहीं सरकार शिक्षकों की भर्ती करने की बजाय 108000 (90 प्रतिशत) सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना है। ऐसी स्थिति में इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार जनआंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। उन्हांने सभी से इस आंदोलन को विकसित करने और आगे बढ़ाने की अपील की।

बैंकों से नकद लेन-देन पर भारी शुल्क थोपने की नितांत गैर-जनवादी जनविरोधी नीति की एसयूसीआई(सी) ने तीव्र निन्दा की

नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने की आड़ में हालांकि इस पर भी शुल्क लगता है, कुल मिलाकर चार बार नकद निकासी और पैसा जमा कराने के बाद तीन निजी बैंकों द्वारा भारी शुल्क लगाए जाने के अति गैर जनवादी फैसले की एसयूसीआई(सी) ने गत 2 मार्च को जारी बयान में घोर निन्दा की। यह फैसला आम नागरिकों, खासकर दिहाड़ी मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों और फेरीवालों के लिए भारी नुकसानदायक, परेशानी भरा और दण्डात्मक होगा जो नकद लेन-देन पर ही निर्भरशील हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार और आर.बी.आई. के कहने पर ही यह कदम उठाया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित अन्य बैंकों द्वारा भी जल्द ही इसका अनुसरण किया जाएगा। सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण होने ही वाला है। आम आदमी पर दिन दहाड़े डकैती डालने की यह एक मुँह बोलती मिसाल है और यह अपने पैसे का मनमर्जी से इस्तेमाल करने के अधिकार का हनन है। इसके अलावा फिलहाल जो ट्रेण्ड चल रहा है।, यह उसी की निरन्तरता है जिसमें आर्थिक मामलों पर मुख्य नीतिगत फैसले बजट के बाहर लिए जा रहे हैं।

उत्पीड़ित लोगों को इस सच्चाई को आत्मसात करना चाहिए कि यदि इस प्रकार के आर्थिक हमलों को बिना सशक्त संगठित प्रतिवाद के अपने ऊपर थोपने दिया गया तो ऐसे हमलों का बाढ़द्वार खुल जाएगा जो बेरहम शोषणमूलक पूँजीवादी शासन के तहत पहले से ही बदहाली और कंगाली से ग्रस्त उनके जीवन को और भी तार-तार कर देंगे।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503